

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

1.1 विश्व के कई हिस्सों में संक्रमणों की नई लहरों एवं कोविड – 19 के बदलते रूपों, टीकाकरण (वैक्सीनेशन) की धीमी गति और टीके को लेकर घोर संरक्षणवाद से जूझता वैश्विक व घरेलू परिदृश्य एक बार फिर विकट हो गया है तथा घोर अनिश्चितता और अधोमुखी जोखिमों से घिरा हुआ है। 23 मई 2021 तक विश्व में संक्रमण के 167 मिलियन से अधिक पुष्ट मामले आए तथा 3.4 मिलियन से अधिक मौतें हुई जिसमें भारत में संक्रमण के मामले 26 मिलियन से अधिक और मृत्यु की घटनाएं 3,03,720 थीं। देशों का अनुभव उत्तरोत्तर यह रेखांकित कर रहा है कि युद्धस्तर पर तेज और विश्वव्यापी टीकाकरण की आवश्यकता सर्वोपरि है – वायरस जब तक मनुष्यों के साथ है, तब तक रूप बदलता रहेगा; जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं।

1.2 महज एक वर्ष पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) ने कोविड-19 को जब महामारी<sup>1</sup> घोषित किया और मार्च में भारत ने एक कठोर लॉकडाउन लगाया, एक गहरा नैराश्य और जोखिम के प्रति भीषण मानसिक भय व्याप्त हो गया। तब से, जिंदगियां खो गई हैं, बची हुई जिंदगी तितर-बितर हो गई है और जीवन शैलियों में आधारभूत परिवर्तन हो गया है। भारत में गतिविधि के कुछ क्षेत्रों में विशेषतः जो संपर्क-गहन हैं, गहरी चोटें आई हैं जबकि दूसरों जैसे कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, सूचना प्रौद्योगिकी, हाइवे आधार-संरचना, ट्रैक्टर बिक्री, रेलवे

मालभाड़ा, विद्युत मांग और घरेलू व्यापार ने महामारी के समक्ष एक दुर्लभ सुदृढ़ता दिखाई है। फैक्टरी-आधारित विनिर्माण और संस्थागत सेवाओं में, महामारी में अपेक्षित तौर-तरीकों को व्यापक तौर पर अपनाया गया जिससे कार्य-प्रक्रियाएं अन्य क्षेत्रों की तुलना में जल्दी सामान्य हुईं। जीवन व जीवन यापन पर आघात के अलावा, उत्पादन व रोजगार की क्षति की ऐसी चोट वर्ष 2020 पर पड़ी जो इतिहास में, विश्व में और भारत में अभूतपूर्व है। यह महामारी अत्यंत अन्याय-संगत भी सिद्ध हुई – आकलन है कि दुनिया भर में वर्ष के दौरान लगभग 95 मिलियन और अधिक लोग घोर गरीबी में धकेल दिए गए, अल्पपोषितों में और 80 मिलियन जुड़ गए तथा इनमें से अधिकांशतः अल्प-आय वाले देशों में।<sup>2</sup>

1.3 महामारी में जहाँ आकस्मिकता व विध्वंसक तेजी थी वहीं इसका नीतिगत प्रत्युत्तर अभूतपूर्व था और अपनी पहुँच में व्यापक। दुनिया भर की सरकारों व केंद्रीय बैंकों ने अतिरिक्त राजकोषीय व्यय, राजस्व त्याग, पूँजी और ऋण समावेश, आकस्मिक देयताओं और उधार दिए जाने के लिए चलनिधि/ फंडिंग के रूप में उठाए गए कदमों के तौर पर कुल यूएस\$ 16 ट्रिलियन<sup>3</sup> या विश्व जीडीपी के 15.3 प्रतिशत के बराबर की कार्रवाई की। भारत में नपा-तुला नीतिगत प्रोत्साहन गरीबों को नकद व वस्तु के तौर पर सीधी सहायता के रूप में प्रारंभ हुआ और उत्तरोत्तर एक व्यापक पैकेज (आत्मनिर्भर भारत) के रूप में विस्तृत हुआ ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सपोर्ट

\* बैंक के लेखांकन वर्ष के परिवर्तित होकर अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) हो जाने से, यह वार्षिक रिपोर्ट नौ महीनों (जुलाई 2020 - मार्च 2021) की परिवर्तन अवधि में रिज़र्व बैंक के कामकाज व कार्यपद्धति से संबंधित है। उपलब्धता के अनुसार रिपोर्ट मार्च 2021 के बाद तक अद्यतन की गई है।

<sup>1</sup> विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को 30 जनवरी 2020 को एक 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति' घोषित किया, और 11 मार्च 2020 को एक 'महामारी'।

<sup>2</sup> आईएमएफ, (2021), 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक – मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज' अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., अप्रैल।

<sup>3</sup> आईएमएफ, (2021) 'फिस्कल मॉनिटर – ए फ़ेयर शॉट', अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी., अप्रैल।

मिले। 2020-21 में संचयी रूप में यह जीडीपी के 15.7 प्रतिशत तक गया जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा चलनिधि व अन्य कार्रवाइयां भी शामिल हैं।

1.4 एक बार पुनः, केंद्रीय बैंक रक्षा की प्रथम पंक्ति बने और उन्होंने अपने विगत अनुभवों के आधार पर विभिन्न पारंपरिक व अपारंपरिक हस्तक्षेप तैयार किए व कार्यान्वित किए। वे अपरिचित क्षेत्रों में भी गए तथा ब्याज दरों को नए निम्न स्तरों तक ले गए, आस्ति क्रय कार्यक्रम प्रारंभ किए, पात्र प्रतिपक्षियों के दायरे को व्यापक किया व संपार्श्विक मानकों को आसान किया, रिपो परिचालनों के मान व अवधि को बढ़ाया और विनियामक ढील के रूप में राहत दी। मौद्रिक और समष्टि-आर्थिक नीतियों के रुख में परोक्ष व प्रत्यक्ष भावी मार्गदर्शन ने इन कार्रवाइयों के पूरक का काम किया। रिज़र्व बैंक ने भी कई कदम उठाए, प्रणाली-व्यापी तथा संस्था-माध्यम (इनस्ट्रूमेंट) - और क्षेत्र-विशेष में भी, ताकि आर्थिक गतिविधि में तेज गिरावट को रोका जा सके, वित्तीय स्थितियां सुगम की जा सकें तथा विशेषतः, वित्तीय बाजारों और मध्यस्थों का सामान्य कार्य सुनिश्चित हो और साथ ही वित्तीय स्थिरता तथा भुगतान व निपटान प्रणाली की मजबूती और मानकबद्धता (इंटिग्रिटी) संरक्षित व बनाई रखी जा सके। समग्र तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को 6 फरवरी 2020 से (5 मई 2021 तक) कुल ₹15.7 लाख करोड़ (2020-21 नामिक (नॉमिनल) जीडीपी का 8.0 प्रतिशत) का सहयोग घोषित किया गया।

1.5 कुल मिलाकर, महामारी संबंधी नीतियों ने काम किया है। संकट के प्रारंभ में जो घरेलू व वैश्विक वित्तीय स्थितियां ठिठक गई थीं, केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों के बाद उनसे प्रतिसाद मिला। सरकारी व कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल नरम होकर ऐतिहासिक निम्न स्तर पर आ गए और स्प्रेड घट गए। जोखिम की भूख लौटी एवं एक आस्ति वर्ग के रूप में उदीयमान बाजार लोकप्रिय बन गए और इस प्रकार पूँजी प्रवाह गतिमान हुए। कुल मिलाकर, वित्तीय स्थितियों के सुगम होने से महामारी के आघात के विस्तार को रोकने में सहायता मिली। मुड़कर देखने पर, यह स्पष्ट है कि बिना इस असाधारण नीतिगत सहायता के, महामारी का प्रभाव कहीं अधिक बुरा होता।

1.6 2020 की दूसरी तिमाही में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अचानक धड़ाम से गिरीं और संकुचन की अभूतपूर्व गहराई में चली गईं, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आशा से अधिक तीव्रता से एक सुदृढ़ समुत्थान भी घटित हुआ। वित्तीय बाजारों को संस्फीति व्यापार (रिफ्लेशन ट्रेड) एवं जोखिम प्रवणता की हवा लगी, इक्विटी बाजार नई ऊँचाइयों पर पहुँचे, बॉण्ड यील्ड नरम पड़ने लगे और कमजोर हो रहे यूएस डॉलर की तुलना में अधिकांश मुद्राओं की मूल्य वृद्धि हुई।

1.7 भारत में भी, शीघ्र समुत्थान अर्थव्यवस्था को 2020-21 की प्रथम तिमाही (2020 की ति2) में एक अभूतपूर्व संकुचन से बाहर निकालकर ति3 (2020 की ति4) तक धनात्मक क्षेत्र में लेकर आया जिसमें रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपायों द्वारा सृजित अनुकूल वित्तीय स्थितियां सहायक हुईं। समुत्थान को पटरी पर आते देख, इक्विटी बाजार उत्साहित हुए और बीएसई सेंसेक्स मार्च 2020 के निम्न स्तरों से 95 प्रतिशत ऊपर उठा (24 मई 2021 तक)। 2020-21 की ति2 और ति3 में कंपनी प्रदर्शन मजबूत रहा तथा व्यय में कमी ने बिक्री में संकुचन की भरपाई यूँ की कि लाभअर्जकता में अच्छा सुधार हुआ। वित्तीय बाजारों ने ऊर्जा पुनः प्राप्त की, इक्विटी मूल्यांकन बढ़े, बॉण्ड प्रतिफल नरम पड़े व दायरे में रहे तथा भारत के पूँजी प्रवाहों का पसंदीदा ठिकाना बन जाने के कारण भारतीय रुपया मूल्यवर्धी रुख के साथ ट्रेड हुआ। फरवरी 2021 में जब नए संक्रमण कम और स्थिर होने लगे थे ऐसा प्रतीत हुआ मानो भारत महामारी का सबसे बुरा दौर पीछे छोड़ आया है जबकि दुनिया के देशों में दूसरी लहरों व लॉकडाउन के अनुभव प्रारंभ हो चुके थे।

1.8 मार्च 2021 से यह सब हठात् बदल गया और इस प्रकार घातक भी रहा। विश्व में सर्वाधिक मामलों तथा सर्वाधिक दैनिक नए संक्रमणों के बीच घिरे भारत ने अपने टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। चिकित्सा आपूर्तियों व कच्चे माल तथा अस्पताल रूपी बुनियादी संरचना की कमी को पूरा करने के प्रयास भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। विनियामक - नेशनल फ़ार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) और

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएसओ) - कोविड-19 उपचार की दवाओं की मांग, आवाजाही, लागत व कीमत निर्धारण की निगरानी कर रहे हैं तथा केंद्र सरकार दवा का उत्पादन बढ़ाने और इसकी आपूर्ति शृंखला को सुगम करने का प्रयास कर रही है जिसमें राज्यों को उत्पादकों से जोड़ा भी जा रहा है। इस उपचार में एक प्रमुख जीवन-रक्षक दवा रेम्डेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ने पर सरकार ने विनिर्माताओं से संपर्क कर महीने में इसका उत्पादन दुगुना कर मई 2021 में 3 लाख शीशी (वायल्स) प्रतिदिन तक पहुँचाया। इसी प्रकार, कई उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग पर अस्थायी रोक, ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर्स के आयात, ऑक्सीजन व ऑक्सीजन संबंधी उपस्करों पर मूल उत्पाद शुल्क व स्वास्थ्य उपकर हटाने के साथ-साथ नए ऑक्सीजन प्लांट लगाकर क्षमता में और वृद्धि द्वारा चिकित्सकीय ऑक्सीजन के उत्पादन व आपूर्ति में वृद्धि की गई। नीतिगत प्राधिकारी क्षेत्र-केंद्रित प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। अल्पावधि परिदृश्य अनिश्चित है जिसमें अधोमुखी जोखिमों और वैश्विक प्रभाव-विस्तार के संभावित परिणामों की प्रमुखता है पर हलचल भरे विगत वर्ष से कुछ सीखने और अनुकूलन करने को मिला है। प्राप्त सबक के आधार पर, भारत आगामी वर्ष की तैयारी विश्वास और धैर्य के साथ कर सकता है। तीव्रतर गति से टीकाकरण महामारी से बचाव की कुंजी है। यह आवश्यक है कि इसे केंद्र में रखकर ऐसी रणनीतियां बनाई व कार्यान्वित की जाएं जो समष्टि-आर्थिक व वित्तीय स्थिरता के साथ दृढ़ व सतत विकास के सुरक्षित पथ पर हमें वापस ले कर आए ताकि भारत अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने में पुनः जुट जाए।

### 2020-21 के अनुभव से सबक

1.9 मुड़कर देखें तो, कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जीवन में एक बार आने वाले ऐसे संकट का प्रहार किया जिसने विश्व के कई देशों में समस्त आकलनों को धता बता दिया और ऐसी गिरावट लेकर आया जो सबसे नैराश्यपूर्ण अनुमानों से भी गहरी साबित हुई। जनवरी 2020 में जब से डब्ल्यूएचओ द्वारा

इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया गया तब से संक्रमण ने दुनिया में बड़ी उग्रता से फैलकर कठोर लॉकडाउन के लिए बाध्य किया जिससे गतिविधियों में और भी बड़े व्यवधान आए तथा साथ ही परीक्षण व अस्पताल की गहन देख-भाल क्षमता के लिए संक्रमण की इतनी बड़ी संख्या एक चुनौती बन गई। 2020 की पहली तिमाही में विश्व में जीडीपी के परिणाम उम्मीद से बुरे थे, पर इसके कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी थे जिसमें भारत एक था। तथापि, दूसरी तिमाही में तो महामारी के ज्वार ने सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ एक अभूतपूर्व रूप से गहराई में डूबा दिया। अन्य मंदियों के विपरीत, निजी उपभोग मांग, सेवा उत्पादन और श्रम बाजार, विशेषतः अल्प कौशलवाले श्रमिक जिनके पास घर से काम करने का विकल्प नहीं है, एक उल्लेखनीय छंटनी में चले गए जिसमें सामाजिक दूरी, गतिविधि व आवाजाही प्रतिबंध, आय की भारी क्षति तथा बुरी तरह चोट खाए उपभोक्ता विश्वास जैसे कारण शामिल हैं। मांग के हवा हो जाने, आपूर्ति शृंखला व्यवधानों तथा भविष्य में कमाई को लेकर निराशा के चलते कारोबार ने निवेश में कटौती कर दी। इस प्रकार, महामारी ने, व्यापक आधार के समग्र मांग आघात और लॉकडाउन-जनित आपूर्ति आघात का मिश्रण पैदा किया। मांग के कमजोर होने, देशों के बीच पर्यटन के ढह जाने, आपूर्ति विस्थापनों व व्यापार प्रतिबंधों के कारण व्यापार बड़ी तेजी से संकुचित हुआ।

1.10 दूसरी तिमाही के अंत की ओर और तिसरी तिमाही में, कई देशों में संक्रमण घटे। अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुलने और आवाजाही के बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलने लगी। समग्र तौर पर गतिविधि, आशा से अधिक तीव्रता से सामान्य हुई और निजी उपभोग में सबसे मजबूत उछाल आया। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी उत्पादन की वृद्धि ने चौंकाया जिसमें सार्वजनिक अंतरणों व निवेश का सहयोग रहा। गतिविधि के पुनः प्रारंभ होने तथा बाह्य मांग में मजबूत वृद्धि के साथ वैश्विक व्यापार सुधरने लगा।

1.11 तथापि, सितंबर के अंत की ओर, महामारी फिर से फैलने लगी तथा विश्व में पुष्ट संक्रमणों की संख्या 34 मिलियन

तक पहुँच गई और एक मिलियन से अधिक मौते हुईं। इसके अतिरिक्त, जहाँ संक्रमण वक्र सपाट हो चुका था, वहाँ भी नई लहरें आने लगीं। परिणामतः, देशों को फिर से खोलने की गति धीमी करनी पड़ी और लॉकडाउन फिर से बहाल करना पड़ा जिसके चलते चौथी तिमाही में फिर से जीडीपी में वैश्विक हुआ। दिसंबर के अंत तक, कई वैक्सीन अनुमोदनों तथा कुछ देशों में वैक्सीन के आ (लॉन्च हो) जाने से आशा बंधी। महामारी संबंधी तौर-तरीकों के अपनाए जाने तथा कुछ देशों द्वारा अतिरिक्त नीतिगत कदम उठाए जाने से, वर्ष 2021 की मजबूत शुरुआत की परिस्थितियां बनीं।

1.12 वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन, महामंदी के बाद से, (-) 3.3 प्रतिशत के सबसे गहरे संकुचन में डूब गया जिसमें उन्नत देशों की जीडीपी 4.7 प्रतिशत और उदीयमान व विकासशील देशों (ईएमडीई) की 2.2 प्रतिशत नीचे गई। वस्तुओं व सेवाओं की विश्व व्यापार मात्रा 8.5 प्रतिशत कम हुई। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आधी हो गई परंतु ईएमडी में मोटे तौर पर वर्ष-दर-वर्ष अपरिवर्तित रही जो ईंधनेतर पण्य वस्तु कीमतों में मजबूती का सूचक है। दूसरी ओर क्रूड की कीमतें वर्ष के दौरान लगभग 33 प्रतिशत नीचे गिरीं।

1.13 2020-21 में घरेलू घटनाक्रम की बात करें तो, मार्च 2020 में रिजर्व बैंक महामारी मुद्रा (पैंडेमिक मोड) में आ गया। अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के तहत, 200 से अधिक अधिकारियों, स्टाफ और सेवा प्रदाताओं की एक टीम को विलगीकरण (आइसोलेशन) में 24x7 कार्य करने के लिए क्वारन्टाइन किया गया ताकि देश के लिए आवश्यक वित्तीय बाजार और भुगतान सेवाएं उपलब्ध रहें। एक वैकल्पिक कार्य क्षेत्र स्थल (एडब्ल्यूएस/आवास) से समय-संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) के सुचारु रूप से चलने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों के कई दल बनाए गए। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/व्यवसायों द्वारा बीसीपी के देश-व्यापी प्रयोग में तकनीक का अधिकाधिक सहारा लिया गया। संकट प्रबंधन के इन प्रयासों से वित्तीय बाजारों व संस्थाओं का बाधा-रहित 24x7 कार्य, मुद्रा का पर्याप्त मात्रा में संचलन, अबाध व सुरक्षित

भुगतान व निपटान प्रणाली- थोक एवं खुदरा दोनों, तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन व बाह्य निवेशों सहित वे सभी कार्य सुनिश्चित हुए जो रिजर्व बैंक राष्ट्र हित में करता है।

1.14 अपनी पहली लहर में महामारी का प्रकोप ति1:2020-21 में चरम पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष-दर-वर्ष 24.4 प्रतिशत संकुचित हुई, जो जी-20 देशों में सबसे गहरी गिरावट रही। तथापि, अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के सघन प्रयासों, आवाजाही के प्रतिबंधों में क्रमिक ढील, मौद्रिक व चलनिधि सुगमीकरण और राजकोषीय सहयोग से दूसरी तिमाही (ति2) में संकुचन कम होने लगा। तीसरी तिमाही (ति3) तक भारत तकनीकी मंदी से बाहर निकल चुका था। फरवरी 2021 के अनुमानों में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने अपने फरवरी 2021 अनुमानों में कहा कि पूरे वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी 8.0 प्रतिशत संकुचित हो चुकी होगी जो 1980-81 के बाद से प्रथम संकुचन है और जब से राष्ट्रीय लेखा संकलित किए जा रहे हैं तब से अब तक का भीषणतम।

1.15 निजी उपभोग जीडीपी में 56 प्रतिशत का योगदान करता है और यह घरेलू मांग की दृढ़ आधारशिला है। तथापि, महामारी के दौरान, निजी उपभोग अभूतपूर्व संकुचन में डूब गया। शहरी मांग में कटौती बनी रही और अपने प्रतिपक्षी ग्रामीण मांग से कम रही। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) ने एक संकट-प्रभाव-प्रतिकारी की भूमिका निभाई और सकल मांग को ठीक किया। जीएफसीई को छोड़ दें तो, जीडीपी पहली तिमाही (ति1) में 29 प्रतिशत नीचे गया होता और 2020-21 में पूरे वर्ष 9.3 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, केंद्र के पूँजीगत व्यय में वृद्धि ने, दो तिमाहियों के अंतराल के बाद, सकल पूँजी निर्माण में थोड़ी वृद्धि के लिए सहायक परिस्थितियां बनाई और समग्र आर्थिक गतिविधि को ति3 में संकुचन से वृद्धि की ओर ले गई। तथापि, वर्ष के लिए समग्र स्तर पर पूँजी निर्माण महामारी-पूर्व के स्तरों से नीचे बना हुआ है। पूँजीगत व्यय को पुनरुज्जीवित करने की योजनाएं जब फलीभूत होंगी तो वे 2021-22 में वृद्धि के महत्वपूर्ण उत्तोलक हो सकती हैं। निवल निर्यात ने 2020-21 में सकल मांग में धनात्मक योगदान दिया,

पर मुख्यतः निर्यात की तुलना में आयात में अधिक संकुचन के कारण। प्रत्याशा है कि 2003-04 के बाद पहली बार वर्ष के लिए समग्र रूप में चालू खाता शेष थोड़ा अधिशेष दर्ज करेगा। अप्रैल-दिसंबर 2020 में निवल पूँजी प्रवाह जीडीपी का 2.7 प्रतिशत रहा और चालू खाते से वित्तपोषण आवश्यकता के अभाव में, विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी वृद्धि हुई।

1.16 इन घटनाओं में संयतकारी सीख है। प्रथम, स्वास्थ्य संकट ने दिखाया है कि हम कितने वैश्विक हैं, न केवल वायरल संक्रमणों के प्रति अपनी कमजोरी में बल्कि टीकों के उत्पादन व साझा करने के तरीके में भी। पृथ्वी से कोविड-19 के उन्मूलन में वैश्विक प्रयास लगे ताकि सभी को टीका लग सके। द्वितीय, वित्तीय संकट की तुलना में वास्तविक अर्थव्यवस्था पर स्वास्थ्य संकट का प्रभाव अधिक व्यापक, अड़ियल और कमजोर करने वाला हो सकता है। सतर्कता में शिथिलता संकट ला सकती है; यही सबसे बेहतर है कि भविष्य की लहरों की तैयारी की जाए। 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गाथा में निजी निवेश का पृष्ठ गायब है; इसमें प्राण फूँकने के लिए ऐसा परिवेश चाहिए जिसमें सहज वृत्तियाँ (एनिमल स्पिरिट्स) पुनः जागृत हों एवं उद्यमी ऊर्जाएं प्रवाहित हों ताकि उत्पादन-पूर्व व उत्पादनोत्तर सहबद्धताएं और गुणक एक टिकाऊ निवेश-चालित समुत्थान की भूमि तैयार कर सकें। अब तक के सबसे बड़े पूँजीगत व्यय और कारोबार को बेहतर ढंग से करने पर जोर के साथ राजकोषीय नीति, निजी निवेश के अंतरगमन (क्राउडिंग इन) की भूमिका में जुट गई है। भारतीय उद्योग के लिए मैदान में उतरना अब उपयुक्त होगा। कुल जीडीपी में जीएफसीएफ का हिस्सा ति3:2020-21 में 33.0 प्रतिशत पर छह-तिमाही की ऊँचाई पर पहुँचा लेकिन ति2: 2008-09 के 36.1 के इसके शिखर से तुलना करें तो अभी भी कुछ और ऊँचाई शेष है। बचत में भी संस्थागत क्षेत्रों में, संरचनागत परिवर्तन हो रहे हैं जो आर्थिक गतिविधि के सामान्य होने का प्रतिबिंब है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि गृहस्थ (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत ति1 की 21.0 प्रतिशत की ऊँचाई से ति3: 2020-21 में 8.1 प्रतिशत पर आ गई – महामारी को देखते हुए

एहतियात और विवशता में की गई बचत खर्च हो रही थी। साथ ही, धारित आय में उछाल वित्तेतर कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को बढ़ावा दे रही है तथा इसमें तीसरी तिमाही में तेज वृद्धि हुई। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय संक्रांति पर है। सार्वजनिक व निजी निवेश का सही मिश्रण इस समय निवेश में चिंगारी पैदा कर सकता है और इस अनूठे मोड़ पर अर्थव्यवस्था के होने का लाभ उठाते हुए सतत वृद्धि का मार्ग तैयार किया जा सकता है - विश्व में तीव्रतम वृद्धि की अर्थव्यवस्था के अपने स्थान को फिर से पाने का निर्णायक मोड़ उसके लिए जो क्रय शक्ति समता में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी है तथा जिसके लिए जनसांख्यिकीय संचरण के विलंबित लाभांश अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और बाह्य स्थिति सुदृढ़ है।

1.17 व्याप्त निराशा के बीच कुल आपूर्ति स्थितियों को कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन का अवलंब मिला। 2020-21 में कृषि व सम्बद्ध कार्यकलाप भारतीय अर्थव्यवस्था के चमकते सितारे के रूप में सामने आए। लगातार तीसरे वर्ष पर्याप्त मानसून वृष्टि मिली और खाद्यान्न व बागबानी उत्पादन में नए रिकॉर्ड बने जिससे समग्र रूप से इस क्षेत्र के उत्पादन में प्रवृत्ति (ट्रेंड) से अधिक विस्तार हुआ। खाद्यान्न भंडार, चावल के लिए बफर मानकों के 6.5 गुना और गेहूँ के लिए 2 गुना बढ़े जिससे ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में खाद्य सुरक्षा और पुख्ता हुई पर भंडार प्रबंधन के लिए कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं। कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन के बाहर रखने के विवेकपूर्ण निर्णय ने बुवाई व कटाई चक्रों में व्यवधान नहीं आने दिया। दूसरे देशों से अलग, भारत को बड़े पैमाने पर विपरीत प्रवास की समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि कोविड-19 को शुरुआत में व्यापक तौर पर एक शहरी रोग माना गया। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए 125 दिनों के अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था और साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने श्रमिकों के विस्थापन को संभालने में सुरक्षा तंत्र का काम किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न प्रयासों द्वारा कृषि क्षेत्र को सीधे प्रोत्साहन भी

दिया गया गया यथा, एक कृषि आधार-संरचना निधि, एक पशुपालन आधार-संरचना विकास निधि, किसान रेल और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)।

1.18 महामारी काल में भारतीय उद्योग की यात्रा भीषण क्षति एवं अवसर दोनों की रही है। विनिर्माण को सबसे बुरा संकुचन झेलना पड़ा और उत्पादन क्षति ति1 में अधिक केंद्रित रही। आपूर्ति बाधाओं से ग्रसित खनन क्षेत्र शिथिल बना रहा और 2011-12 के बाद 2020-21 में सर्वाधिक संकुचन आया। महत्वपूर्ण आधार-संरचना व उपस्कर के अभाव और महामारी में परिचालनगत दिक्कतों के कारण कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस का उत्पादन घट गया। साथ ही, महामारी ने औषधीय पदार्थों (फार्मास्यूटिकल्स) के विस्तार के लिए अवसर खोल दिए। थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए लाई गई उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएसआई) योजना का उद्योग ने अच्छा स्वागत किया है और उम्मीद है कि घरेलू स्तर पर औषधीय पदार्थों के उत्पादन व चिकित्सा निर्यात को इससे सहयोग मिलेगा। मोटर-गाड़ी उद्योग (ऑटोमोबाइल्स) ने भी अच्छी वृद्धि दर्ज की। महामारी के चलते सार्वजनिक यातायात की जगह उपभोक्ताओं द्वारा निजी गाड़ियों को तरजीह दिए जाने का फायदा यात्री कार और दुपहिया वर्ग को मिला। औद्योगिक गतिविधि की दूसरी उत्साहवर्धक विशेषता बिजली उत्पादन की शीघ्र शुरुआत और वर्ष के उत्तरार्ध में उसकी मजबूत वृद्धि रही। तथापि ति4:2020-21 में, औद्योगिक क्षेत्र फिर पिछे खिसक गया तथा समग्र उत्पादन में जनवरी 2021 में 0.9 प्रतिशत एवं फरवरी में 3.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ। अगस्त 2020 से, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक विस्तार में रहा है जो बेहतर संभावना का संकेत दे रहा है पर वर्तमान परिस्थितियां कमजोर व अस्थिर बनी हुई हैं।

1.19 महामारी की शुरुआती अवधि में संपर्क गहन सेवाओं में गतिविधि के लगभग रुक जाने से सेवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। यद्यपि विमानन, पर्यटन और आतिथ्य जैसे संपर्क गहन क्षेत्रों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी, अन्य क्षेत्रों में उच्च आवृत्ति संकेतकों ने प्रत्याशा से तेज समुत्थान की ओर इशारा

किया। वर्ष की दूसरी छमाही में ई-वे बिलों में सतत सुधार तथा मजबूत जीएसटी संग्रह ने संकेत दिया कि घरेलू व्यापारिक गतिविधि में समुत्थान प्रारंभ हो चुका है। प्राथमिक क्षेत्र की तरह आईटी जैसे अति-तृतीयक उद्योगों ने महामारी के बीच अच्छी सृष्टि दिखलाई है। भौतिक आधार-संरचना के विस्तार की गति बनाए रखने पर जोर के कारण ताकत का दूरा क्षेत्र बना निर्माण – प्रतिदिन 37 किलोमीटर के निर्माण के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ने 13,000 किलोमीटर के नए रिकॉर्ड को छू लिया। आवास के लिए मांग में जान फूँकने में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकदी रहित टोल संग्रह की ओर बढ़ते हुए फरवरी 2021 में आवश्यक किए गए फास्टैग से मूल्य व मात्रा दोनों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) की मजबूत वृद्धि देखने को मिली। स्टार्ट-अप्स की लहर और डिजिटलीकरण के बढ़ते ज्वार के दम पर महामारी के दौरान ई-कॉमर्स फूला-फला। बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए ईंट-गारे वाले उद्यमों ने भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की।

1.20 सेवा क्षेत्र अभी भी घायल है। 2020-21 की चौथी तिमाही (ति4) में, विभिन्न उप-क्षेत्रों में महामारी से बाहर निकलने के बहु-गति मार्गों से परिदृश्य उज्ज्वल हो रहा था। अप्रैल 2020 में सेवा पीएमआई ने अपना सबसे गहरा संकुचन देखा, पर उसके बाद धीरे-धीरे यह संभला, अक्टूबर से विस्तार क्षेत्र में गया और लगातार सात महीने से वहाँ टिका हुआ है। महामारी ने श्रम बाजार उजाड़ दिए और इसमें सबसे बड़े आघात झेले स्व-नियोजित और अनियत मजदूरों ने। लॉकडाउन में ढील और प्रवासी श्रमिकों के महानगरों में लौटने से, रोजगार सामान्य होने की ओर बढ़ने लगा था, जैसा कि गृहस्थों (हाउसहोल्ड्स) के सर्वेक्षणों, पे रोल आँकड़ों और दूसरी लहर के पहले कॉरपोरेट क्षेत्र में नई शुरुआतों पर आ रहे डेटा को देखने से पता चलता है।

1.21 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश ने आपूर्ति व्यवधान पैदा किए और वर्ष के अधिकांश समय में खाद्य मुद्रास्फीति उँचाई पर बनी रही। ताड़ के तेल (पाम

ऑयल) के आयात पर भारत की बड़ी निर्भरता के कारण वैश्विक खाद्य तेल की चढ़ती कीमतों से कीमत दबाव बढ़े। मई 2020 में पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के अनिवर्ती प्रभाव (रैचेट इफेक्ट), वर्ष के प्रथमार्ध में वैश्विक स्वर्ण कीमतों में वृद्धि, विपरीत प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन) के कारण श्रमिकों की कमी तथा अतिरिक्त संरक्षा (सेफ्टी) उपायों ने लागत दबाव बढ़ाए और मूल (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति को मजबूत किया। इसके अतिरिक्त, खोई कमाई को फिर हासिल करने के लिए मार्जिन बढ़ाए गए; सामान्यतः महामारियों में खुदरा बाजार कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं क्योंकि सामाजिक दूरी की आवश्यकता के कारण उपभोक्ता आस-पास कम कीमतों की खोज नहीं कर पाते। इन समस्त कारकों के फलस्वरूप, वर्ष के प्रथम आठ महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपर रही-अप्रैल और मई में भी, जब संतोषजनक डेटा संग्रह के अभाव में डेटा प्रतिस्थापित किए गए। नवंबर 2020 – जनवरी 2021 के दौरान जाड़े में खाद्य कीमतों की मौसमी कमी के कारण थोड़ी नरमी के बाद, फरवरी-मार्च 2021 में मुद्रास्फीति अपने ऊर्ध्व रुझान पर लौट आई क्योंकि मूल मुद्रास्फीति ऊँचाई पर डटी रही। इन प्रभावों और वैश्विक पण्य कीमतों के मजबूत होकर इस रूप में आने से, जिसे व्यापक तौर पर एक दूसरे पण्य महाचक्र (सुपरसाइकल) की शुरुआत माना जा रहा है, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 2019-20 के 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 6.2 प्रतिशत के औसत पर आ गई। वर्ष-दर-वर्ष, मार्च 2021 में वैश्विक ऊर्जा की कीमतें (वर्ल्ड बैंक पिक शीट डेटा) 89.7 प्रतिशत बढ़ीं, खाद्य कीमतें 29.4 प्रतिशत, धातु और खनिज कीमतें 60.4 प्रतिशत और मूल्यवान धातु कीमतें 16.3 प्रतिशत बढ़ीं। इस प्रकार क्षमता की तुलना में मंद पड़ी आर्थिक गतिविधि और लक्ष्य से ऊपर बनी हुई मुद्रास्फीति के बीच कठिन दुविधा का सामना भारत को करना पड़ा जहाँ प्रत्येक विरोधी दिशा में खींचने वाला और मौद्रिक नीति के संचालन को चुनौती देने वाला था।

1.22 इस पृष्ठभूमि में, मार्च-मई 2020 के दौरान पॉलिसी रिपो रेट को 115 आधार अंक कम करते हुए मौद्रिक नीति

समिति (एमपीसी) इसे 4.0 प्रतिशत पर लाई। फरवरी 2019 – फरवरी 2020 के बीच नीतिगत दरों में 135 अंकों की कटौती को लें, तो वर्तमान सुगमकारी चक्र में नीतिगत दर में कुल कटौती 250 आधार अंकों (बीपीएस) की रही है। चलनिधि अधिशेष की परिस्थितियों और चुनिंदा क्षेत्रों को अस्थिर दर वाले ऋणों के लिए अधिदेशित बाह्य बेंचमार्क-आधारित कीमत निर्धारण के कारण 2020-21 में मौद्रिक संचरण उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ। ताज़ा रुपया ऋणों (फ्रेश रुपी लोन्स) पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएआर) वर्ष के दौरान 79 आधार अंक (बीपीएस) घटी। एमपीसी ने यह कहते हुए समय-अनुषंगी भावी मार्गदर्शन दिया कि वृद्धि को पुनरुज्जीवित करने तथा अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान और 2021-22 में मौद्रिक नीति निभावी रखी जाएगी और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहे।

1.23 रिज़र्व बैंक ने कई पारंपरिक व अपारंपरिक कदम उठाए ताकि कमजोर क्षेत्रों, संस्थाओं और वित्तीय साधनों को अवलंब देने के लिए पर्याप्त प्रणाली-स्तर चलनिधि और लक्ष्यित चलनिधि सुनिश्चित हो। परिणामतः, विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दरें नरम हुईं, स्प्रेड संकुचित हुए और सहायक वित्तीय स्थितियां कायम हुईं। इससे वित्तीय बाजारों और संस्थाओं को सामान्य रूप से कार्य करने, वर्धित सरकारी उधार कार्यक्रम को 17 वर्ष के न्यूनतम भारित औसत उधारी लागत पर सुसंगत ढंग से पूरा करने और रिकॉर्ड मात्रा में कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने में सहायता मिल पाई।

1.24 जैसा कि पहले कहा गया है, स्पष्ट भावी मार्गदर्शन 2020-21 में मौद्रिक नीति के संचालन की एक नवोन्मेषी विशेषता बना। रिज़र्व बैंक ने इस पर जोर दिया कि वित्तीय बाजार स्थिरता और प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) का सुसंगत विकास सार्वजनिक कल्याण की बाते हैं जिसके लाभ अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों को जाते हैं। ऐसे परिदृश्य में, दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ), लक्ष्यित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सदा-सुलभ (ऑन-टैप) टीएलटीआरओ, म्यूचुअल फंड के लिए एक चलनिधि खिड़की,

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की चलनिधि स्थिति को बेहतर करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा परिचालित एक विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस), राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में भी खुला बाजार परिचालन और द्विदिशात्मक परिचालन (ट्रिस्ट ऑपरेशन्स) सहित विभिन्न उपकरणों (इनस्ट्रूमेंट्स) के माध्यम से रिजर्व बैंक ने बाजार परिचालन किए। इन परिचालनों ने चलनिधि संबंधी भय दूर किए और वित्तीय क्षेत्र के प्रति संभावित प्रणालीगत जोखिम टाले जा सके। स्थितियां जब सामान्य हुईं, एलटीआरओ/टीएलटीआरओ के अंतर्गत पहले उठाए गए फंड को परिपक्वता से पहले लौटाकर नरम ब्याज परिवेश का लाभ उठाने में बैंकों की सहायता की गई। इसके अलावा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंक कम (4.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत) किया गया। आगे, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएएफ) के अंतर्गत बैंकों के उधार लेने की सीमा को बढ़ाते हुए एनडीटीएल से आहरण को 3 प्रतिशत कर दिया गया जो पहले 2 प्रतिशत था। ऋण चुकौती अधिस्थगन के रूप में उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए पूर्वकृत विनियामक उपायों की घोषणा के बाद कोविड-19 से प्रभावित व्यवहार्य खातों के समाधान के लिए व्यापक समाधान संरचना (रिसॉल्यूशन फ्रेमवर्क) 1.0 प्रस्तुत की गई।

1.25 भारत ने विशाल राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिया, जिसका उल्लेख पहले किया गया, और यह अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए क्रमिक व नपा-तुला प्रयास था। परिणामतः, पूँजीगत व्यय ने 2020-21 की पहली छमाही में 11.6 प्रतिशत के संकुचन को उलटते हुए अक्टूबर 2020-फरवरी 2021 के दौरान 104.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। व्यय की गुणवत्ता में यह सुधार उप-राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिबिंबित हुआ और राज्यों का पूँजीगत व्यय (संवितरित ऋणों व अग्रिमों को अलग करके) सुधरकर छ2:2020-21 में महामारी-पूर्व स्तर पर आ गया। दूसरी ओर सरकारी राजस्व 2020-21 में नीचे चला गया तथा विनिवेश से सहयोग के अभाव

में कर राजस्व में चक्रीय व महामारी-जनित कमी और गहरा गई। परिणामतः, व्यय के दबाव से राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 9.4 प्रतिशत जो गया जो 3.5 प्रतिशत के बजट अनुमान से काफी अधिक है।

1.26 बाह्य मोर्चे पर, कोविड-19 महामारी की पहली लहर के आक्रमण से ति1:2020-21 में भारत का वाणिज्य वस्तु व्यापार तेजी से नीचे गया। मध्य-सितंबर से संक्रमणों के घटने के बाद देशों के बीच व्यापारिक गतिविधि की क्रमिक शुरुआत और घरेलू अर्थव्यवस्था को अनलॉक किए जाने से वाणिज्य वस्तु व्यापार समुत्थान के संकेत देने लगा। निर्यात में समुत्थान को दवाइयों व औषधीय पदार्थों (ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स) तथा कृषि के मजबूत प्रदर्शन का सहयोग मिला। प्रजातिगत दवा विनिर्माण क्षमता के दम पर भारत विश्व के लिए औषधीय पदार्थों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरकर आया – अंतरराष्ट्रीय विनियामक निकायों (यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन; वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन – गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस या डब्ल्यूएचओ-जीएमपी; और यूरोपीयन डायरेक्टोरेट ऑफ़ क्वालिटी मेडिसिन्स या ईडीक्यूएम) द्वारा अनुमोदित सबसे ज्यादा औषधीय पौधे भारत के पास हैं। घरेलू माँग के बेहतर होने से वर्ष के उत्तरार्ध की ओर वाणिज्य वस्तु आयात भी बढ़ा। समग्र रूप से वर्ष के लिए वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा यूएस \$ 161.3 बिलियन से वर्ष-दर-वर्ष घटकर यूएस \$ 98.6 बिलियन हो गया। यात्रा व परिवहन प्रतिबंधों के बीच विदेशी माँग में आई कमी सेवाओं के आयात व निर्यात दोनों को नीचे ले गई, जिसमें केवल आईटी-आधारित सेवाओं ने सुदृढ़ता दर्शाई और समग्र निवल निर्यात को अहम सहारा दिया। मेजबान देशों में नौकरी के घटते अवसर एवं आय के गिरते स्तरों के साथ खाड़ी देशों से विपरीत प्रवास का प्रभाव देश में आने वाले धन-प्रेषण के प्रवाह पर पड़ा। वाणिज्य वस्तुओं व अदृश्य मदों में चल रहे घटनाक्रम से छ1:2020-21 में जीडीपी का 3.0 प्रतिशत का चालू खाता अधिशेष घटकर छ2 में जीडीपी के लगभग 0.5 प्रतिशत के घाटे में बदल गया<sup>4</sup>

<sup>4</sup> ति4:2020-21 के अनुमानों के आधार पर।

1.27 वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), विशेषतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जाने वाले प्रवाहों में, गिरावट के बावजूद भारत निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहा और निवल एफडीआई वर्ष के दौरान एक ऊँचाई पर पहुँच गया। कुछ बड़े सौदों के होने से डिजिटल क्षेत्र भारत में एफडीआई का बड़ा प्राप्तकर्ता बना। निवेशकों की भूख जब वापस लौटी तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाहों में भी उछाल आया जिसे आगे बढ़ाने में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों की अति-निभावी मौद्रिक नीति रुख ने मुख्य कारक की भूमिका निभाई।

1.28 रिज़र्व बैंक के लिए बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य एक प्राथमिकता के रूप में उभरा और बैंक ने इसे महामारी के आघात से बचाने के लिए प्रयास किए। इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यशील पूंजी तक सुविधाजनक पहुँच; अधिस्थगन; आस्ति वर्गीकरण में विराम; लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध; व्यवहार्य खातों की पुनर्रचना की अनुमति; और विवेकपूर्ण मानदंडों जैसे कि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के नियोजित रोल-आउट को स्थगित करने के साथ ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अपेक्षा के लिए छूट को आसान बनाना शामिल थे (वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों को रिपोर्ट के अनुबंध I और II में बताया गया है)।

1.29 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (जीएनपीए) मार्च 2020 के 8.2 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 की समाप्ति पर 6.8 प्रतिशत हो गया था। बैंकों द्वारा विवेकपूर्ण प्रावधानीकरण, जो आस्थगन लेने वाले और पुनर्रचना के तहत चल रहे खातों के लिए विनियामकीय निर्धारण से भी अधिक था, के परिणामस्वरूप एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2020 के 66.6 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2020 की समाप्ति पर 75.5 प्रतिशत के साथ बेहतर हुआ। बड़े खाते में डाले जाने के लिए समंजन करते हुए पीसीआर मार्च 2020 के 81.3 प्रतिशत से बढ़कर 88.0 प्रतिशत रहा। एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च-अंत 2020 के 14.8 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर-अंत 2020 में

15.9 प्रतिशत हो गया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बाज़ार से पूंजी जुटाने और प्रतिधारित लाभ से सहयोग मिला। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋण में 5.6 प्रतिशत बढ़त हुई (26 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर), जो एक वर्ष पहले के 6.1 प्रतिशत से कम था। सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश में तेजी आई, तथा इसमें एक वर्ष पहले के 10.6 प्रतिशत की तुलना में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2020 तिमाही में निवल हानि रिपोर्ट करने के बाद, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने बाद की तिमाहियों में आस्तियों पर धनात्मक प्रतिलाभ (आरओए) रिपोर्ट किया। उनके तुलन पत्रों और पूंजीगत स्थितियों की वास्तविक अवस्था विनियामकीय छूटों के वापस लिए जाने पर ही मापी जा सकती है।

1.30 रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान एनबीएफसी और एचएफसी के लिए विनियामकीय ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भी कई कदम उठाए। एनबीएफसी के लिए बैंक ने एक आकार-आधारित विनियामकीय ढांचे की ओर पहल की। विनियामकीय धरातल पर सभी के लिए समान अवसर को बढ़ावा देने की दृष्टि से एचएफसी के लिए अक्टूबर 2020 में एक संशोधित ढांचा लाया गया। एनबीएफसी के लिए चरणबद्ध रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा आरंभ किया गया है, जिसमें चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) भी शामिल है। मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए दिशानिर्देशों की भी व्यापक समीक्षा की गई। एनबीएफसी का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2020 के 6.8 प्रतिशत से बेहतर होकर दिसंबर 2020 में 5.7 प्रतिशत हुआ है, हालांकि ऐसा मुख्यतः, विराम पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में छूट के चलते हुआ है। इसी अवधि के दौरान एनबीएफसी का सीआरएआर भी थोड़ा सुधरकर 23.7 प्रतिशत से 24.8 प्रतिशत हो गया।

1.31 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति और कृषि ऋण पर आंतरिक कार्यदल की संस्तुतियों को लागू किया ताकि समावेश में सुधार लाया जा सके और इन क्षेत्रों तक ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके। उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समंजन के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर संशोधित मास्टर निदेश जारी किए

गए। अर्थव्यवस्था के सेवा रहित और अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए किफायती लागत पर ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सह-ऋण (को-लेंडिंग) की शुरुआत की गई। पूरे देश को चरणबद्ध रूप से कवर करने के लिए प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) का विस्तार आरंभ किया गया।

1.32 रिजर्व बैंक बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पूर्व की तुलना में पर्यवेक्षी रुख अब अधिक भविष्योन्मुखी और मूल-कारण पर केंद्रित है, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रियाओं में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित दिशाओं में पहल की गई (ए) विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए अपेक्षित पर्यवेक्षी कार्यों का समेकन; (बी) क्षैतिज और उर्ध्व दोनों प्रकार के जोखिम मूल्यांकन द्वारा पर्यवेक्षण की विशेषज्ञता और सुदृढीकरण; (सी) क्षमता विकास के लिए समर्पित पर्यवेक्षक महाविद्यालय (कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स) की स्थापना; और (डी) सुपटेक का प्रयोग।

1.33 कोविड-19 महामारी ने भारत में भुगतान परितंत्र के डिजिटल रूपांतरण की गति बढ़ा दी है। तकनीक के उपयोग की व्यापकता में वृद्धि लाने के अतिरिक्त महामारी ने भुगतान के डिजिटल माध्यमों की प्रचुरता को भी बढ़ावा दिया है, जिससे देश 'कम-नकदी' वाले विकल्पों की राह पर बढ़ा है। स्पर्श-रहित लेनदेन और फिनटेक क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा अंतिम उपयोगकर्ता की आवश्यकतानुसार तैयार किए गए वित्तीय उत्पादों की बढ़ती पसंद के साथ डिजिटल लेनदेन तालाबंदी (लॉकडाउन) वाले महीनों के निम्न स्तर से सुधरकर बाकी वर्ष में तेज हुआ। रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा निरंतर नीतिगत सहयोग का मुख्य ज़ोर एक उपयुक्त विनियामकीय नीति बनाने के उद्देश्यों और डिजिटल उधार परितंत्र की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने का संतुलन बनाए रखने पर है।

1.34 दिसंबर 2020 में 24x7 आरटीजीएस के आरंभ ने डिजिटल लेनदेन की तेज और सुरक्षित वृद्धि के लिए सक्षमकारी वातावरण बनाया। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में आ गया है जहां आरटीजीएस प्रणाली वर्ष भर चौबीसों घंटे परिचालित होती है। मार्च 2021 में आरटीजीएस द्वारा थोक लेनदेन 70 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ गए। खुदरा क्षेत्र में, यूनिफाइड

पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में 273 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, साथ ही इसका मूल्य पहली बार ₹5 लाख करोड़ के स्तर से ऊपर गया। अन्य खुदरा भुगतान प्रणालियों की भी मजबूत वृद्धि हुई जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी), भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस), इमीडियेट पेमेंट सर्विस (आइएमपीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)। कुल मिलाकर, 2019-20 के 3,412 करोड़ की तुलना में, 2020-21 में कुल डिजिटल लेनदेन की मात्रा 4,371 करोड़ रही जो महामारी के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल भुगतान प्रणाली की सुदृढ़ता को प्रमाणित करता है।

1.35 2020-21 को इतिहास में जीवन और मानवता के आदर्शों में कोविड-19 महामारी के व्यवधान के वर्ष के रूप में याद किया। इसने आर्थिक गतिविधियों, वित्त और आमतौर पर जीवन और आजीविका को इतनी गहराई और जबर्दस्त रूप से बदल दिया कि सुधार में कई साल लग जायेंगे। महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की आधार-संरचना की भंगुरता और पिछले वर्षों में स्वास्थ्य पर व्यय की अपर्याप्तता को भी उजागर किया। वर्ष 2020 अभूतपूर्व नीतिगत रेस्पॉन्स के लिए भी उल्लेखनीय होगा, जो समन्वित न होते हुए भी वैश्विक रूप से सुसंगत रहे। वैज्ञानिक समुदाय, प्रसंशनीय रूप से, अभूतपूर्व स्तर और गति से जुट गया तथा दिसंबर 2020 तक टीकों का रोलआउट इनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रखरता का प्रमाण है। स्वास्थ्य कर्मियों और अगली पंक्ति के कर्मचारियों का अपनी जान जोखिम में डालकर भी महामारी के नियंत्रण में व्यवस्था को सहयोग देने का निःस्वार्थ और प्रतिबद्ध कार्य इस अनिश्चित समय में अत्यंत सराहना के योग्य है। अब से भारत सहित वैश्विक स्थिति में सुधार और इसका परिदृश्य, टीकाकरण की गति व कवरेज और वायरस के उभरते रूपों पर इसके असर पर निर्भर होगा।

### 2021-22 और उसके बाद का परिदृश्य

1.36 ऐतिहासिक रूप से, इन्फ्लूएंजा संबंधी महामारियों का प्रकोप लहरों में होता है। दुनिया भर में कई देश पहले ही कोविड-19 की दो या दो से अधिक लहरों का अनुभव कर चुके हैं। इनमें से प्रत्येक लहर में प्रतिबंधात्मक उपाय करके जीवन की रक्षा करने और प्रतिबंध न लगाकर आजीविका की रक्षा

करने के बीच का कष्टदायक संतुलन बिठाना पड़ता है। यही दुविधा आज सभी के सामने है, जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घातक लहरें जोर मार रही हैं। भारत इस तलवार की धार सी दुविधा से अछूता नहीं है। महामारी की नियमितताओं के आधार पर बनाए गए गणितीय मॉडलों के इस पूर्वानुमान, कि भारत में दूसरी लहर मोटे तौर पर मई 2021 के मध्य तक चरम पर पहुँचेगी, के अनुरूप हाल में दैनिक नए संक्रमणों की संख्या कम हुई है, लेकिन घटनाएं और परिवर्तन कारक अब भी सुविधाजनक स्तर से ऊपर हैं। इसके परिणामस्वरूप, इस लहर की समष्टि-आर्थिक लागत ति1: 2021-22 तक सीमित हो सकती है, जिसका कुछ प्रसार-प्रभाव जुलाई तक जा सकता है। यही इस समय परिकल्पित किया जा सकने वाला सबसे आशावादी परिदृश्य है – संक्रमण की अगली लहरों का सामना करने के लिए यह महामारी के कठोर प्रोटोकॉल और प्रचालन तंत्र (लॉजिस्टिक्स) तैयार करने, टीकों के उत्पादन और चिकित्सा आपूर्ति में तेजी लाने, स्वास्थ्य आधार संरचना में खामियों को दूर करने और भंडार, विशेषतः टीकों का, जमा करने के लिए एक सीमित अवसर (विंडो) देता है। अन्य सभी परिणामों में जीवन, रोजगार और उत्पादन में होने वाली हानि काफी प्रतिकूल और दीर्घकालिक रहने की संभावना है। भारत के दवा उद्योग के आकार और समुन्नत स्वरूप को देखते हुए निश्चित रूप से आशा है कि भारत अपनी शक्ति का लाभ उठाते हुए भविष्य की लहरों को नियंत्रित कर सकता है।

1.37 स्थिति में असमान वैश्विक सुधार धीरे-धीरे नए संक्रमणों और उत्परिवर्तनों (म्यूटेशन) के बीच अपनी राह बना रहा है और गति पकड़ने के लिए संघर्षरत है। तेजी से और व्यापक रूप से टीकाकरण करने वाले देश संक्रमण वक्र को नीचे ला रहे हैं। वे संभवतः अन्य देशों की तुलना में महामारी की मौजूदा लहर से जल्दी बाहर निकलेंगे और वैश्विक सुधार का नेतृत्व करेंगे, हालांकि सभी को समान रूप से टीकाकरण होने तक वे जोखिम में रहेंगे। सुधार को आधार देने वाली शक्तियां हैं- टीकाकरण अभियान और जहाँ भी गुंजाइश है वहाँ अतिरिक्त नीतिगत समर्थन। इन स्थितियों के अंतर्गत, आईएमएफ ने अप्रैल 2021 के अपने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण (वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक) में 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 6.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान दिया है। अधोमुखी

जोखिम संतुलन बिगाड़ते हैं: महामारी का फिर से उभरना; मुश्किल वित्तीय स्थितियां; लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव; बढ़ता सामाजिक असंतोष; और भू-राजनीतिक तथा व्यापारिक टकराव। आशान्वित करने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2020 में, जी20 ने अधोमुखी जोखिमों से बचाते हुए, लोगों के जीवन, काम और आय की सुरक्षा करने, वैश्विक आर्थिक सुधार का समर्थन करने और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए जब तक जरूरी हो, तब तक उपलब्ध सभी नीतिगत उपाय करते रहने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है।

1.38 2021 में जैसे-जैसे सुधार में मजबूती आयेगी, वैश्विक व्यापार तेज होने की आशा है। आईएमएफ ने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की मात्रा में 8.4 प्रतिशत की बढ़त का अनुमान दिया है (पण्य व्यापार की मात्रा के लिए डब्ल्यूटीओ का अनुमान 8.0 प्रतिशत है), हालांकि वे महामारी-पूर्व की प्रवृत्ति से नीचे बने रहेंगे। सीमापारिय सेवा व्यापार (पर्यटन और परिवहन) के मंद रहने की संभावना है, जब तक कि वैश्विक स्तर पर महामारी कम न हो जाए, अंतरराष्ट्रीय यात्रा महामारी संबंधी प्रतिबंधों में छूट न मिले और विश्वास वापस न आ जाए।

1.39 आर्थिक गतिविधियों में काफी शिथिलता के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और अधिकांश उदयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्रास्फीति कम रहने की उम्मीद है; हालांकि अल्पावधि में, बड़े स्तर पर राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन से और पण्य वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों से ऊर्ध्वमुखी जोखिम उत्पन्न होगा, जैसा कि मुद्रास्फीति प्रत्याशा के बाजार आधारित संकेतक दर्शा रहे हैं। एक वर्ष पहले के महामारी-कालीन न्यून स्तरों की तुलना में अप्रैल 2021 तक, ऊर्जा की कीमतों में 170 प्रतिशत और गैर-ऊर्जा पण्य वस्तुओं (कृषि, उर्वरक, खनिज, धातु और कीमती धातुओं) की कीमतों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.40 भारत में दूसरी लहर में संक्रमण की तेजी चिंताजनक रही है, तथा इस आकार और गति की वृद्धि को संभालने की क्षमता की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य आधार संरचना पर भारी दबाव पड़ा है। दैनिक नए पुष्ट संक्रमणों की संख्या पहली लहर की उच्चतम सीमा को पार कर गई और अप्रैल की शुरुआत में 1 लाख से अधिक हो गई और महीने के अंत तक 4 लाख से

ऊपर भाग जाने के बाद गिरकर 23 मई 2021 की स्थिति के अनुसार 2.2 लाख हुई। स्वस्थ होने के वालों की संख्या संक्रमण के मामलों से कम रही और 23 मई 2021 तक स्वस्थ होने की दर गिरकर 88.7 प्रतिशत हो गई, जबकि चिकित्सकीय रूप से पुष्ट न की गई अधिक मौतों की रिपोर्ट के बीच पुष्ट की गई मृत्यु दर लगभग 1.1 प्रतिशत पर बनी रही। हालांकि शुरुआत में महाराष्ट्र इसके केंद्र के रूप में दिखाई दिया, अगले कुछ हफ्तों में इस दूसरी लहर ने देश के बाकी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, साथ ही पुष्ट मामलों की कुल संख्या 2.6 करोड़ को पार कर गई और 23 मई 2021 की स्थिति के अनुसार 27 लाख से अधिक सक्रिय मामले और 3.03 लाख मृत्यु दर्ज की गई। 23 मई 2021 तक, भारत में कुल पुष्ट की गई कोविड-19 संबंधी प्रति व्यक्ति संचयी मृत्यु दर वैश्विक औसत से 50 प्रतिशत कम रही है। हालिया दूसरी लहर के साथ भारत में सीमांत मृत्यु दर - प्रति मिलियन जनसंख्या पर नई मृत्युओं का 7-दिवसीय औसत - 3.04 प्रतिशत रही जो 1.55 प्रतिशत के कुल वैश्विक औसत से अधिक रही; यद्यपि 7-दिवसीय औसत आधार पर नए संक्रमणों के प्रतिशत के रूप में नई मौतें अभी वैश्विक औसत से 20 प्रतिशत नीचे रहीं।<sup>5</sup>

1.41 तथापि, तबाही के स्तर और मानव जीवन की हानि से अमित दरारें पड़ी हैं और भविष्य के लिए कई सबक मिले हैं: महामारी की तैयारी के लिए निरंतर सतर्कता - यह स्थिति अभी कुछ समय के लिए बनी रहने वाली है; स्वास्थ्य खर्च और स्वास्थ्य आधार-संरचना के उन्नयन की प्राथमिकता; भंडार बनाने के साथ-साथ टीकों का और टीकाकरण का तेजी से रोलआउट; वैक्सीन डेवलपर्स/उत्पादकों को वायरस के नए-नए रूपों द्वारा मिल रही चुनौती के परिप्रेक्ष्य में शोध और विकास में निवेश; स्थानीय लॉकडाउन, गतिशीलता पर प्रतिबंध और अन्य कोविड-उपयुक्त व्यवहार सहित विवेकपूर्ण और पूर्वकृत महामारी प्रोटोकॉल टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने 13 अप्रैल 2021 को भारत में रूस के स्पुतनिक V के उपयोग को मंजूरी दी है। इसके अलावा, टीकाकरण कवरेज का विस्तार करते हुए, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय 1 मई 2021 से टीकाकरण के

लिए पात्र हैं। वैक्सीन निर्माताओं को अपनी आपूर्ति का 50 प्रतिशत तक राज्यों और खुले बाजार को पूर्व-घोषित मूल्य पर जारी करने का लचीलापन दिया गया है। उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने और वैक्सीन उत्पादन में नए खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए वैक्सीन के मूल्य निर्धारण को उदार बनाया गया है। महामारी से लड़ने के लिए उपलब्ध टीकों का समूह बढ़ाने के लिए, सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स (यूएस), यूनाइटेड किंगडम (यूके), यूरोपीय संघ (ईयू), जापान में अनुमोदित और/या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सूचीबद्ध टीकों के भारत में आपात उपयोग के लिए अनुमति दी है। इसके अलावा, सरकार ने टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए वैक्सीन निर्माताओं को ₹4,500 करोड़ रुपये के अग्रिम का अनुमोदन दिया है।

1.42 दूसरी लहर के आरंभ से वृद्धि अनुमानों में संशोधनों का दौर शुरु हुआ है, जिसमें आम सहमति वर्ष 2021-22 के लिए रिजर्व बैंक के 10.5 प्रतिशत के अनुमान की ओर बन रही है - जो ति1 में 26.2 प्रतिशत, ति2 में 8.3 प्रतिशत, ति3 में 5.4 प्रतिशत और ति4 में 6.2 प्रतिशत है। इस संभावना (आउटलुक) के लिए सबसे बड़ा जोखिम स्वयं महामारी ही है, विशेष रूप से दूसरी लहर का प्रभाव और अवधि। फिर भी, पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा वृद्धि, क्षमता उपयोग में वृद्धि और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में बेहतर परिवर्तन के कारण सकारात्मकताएं भी उत्पन्न होती हैं।

1.43 अप्रैल और मई 2021 की शुरुआत के लिए, उपलब्ध उच्च बारंबरता संकेतक एक मिश्रित तस्वीर दर्शाते हैं। गतिशीलता और प्रवृत्ति संकेतकों में जहाँ नरमी आई है, वहीं कई गतिविधि संकेतकों ने अपनी जगह बनाए रखी है और दूसरी लहर के समक्ष सुदृढ़ता दर्शाई है। जीएसटी संग्रह अप्रैल में लगातार सातवें महीने ₹1 लाख करोड़ के आंकड़े के पार रहा और दर्ज किए गए उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। यह दर्शाता है कि विनिर्माण और सेवाओं का उत्पादन बना रहा है। वहीं दूसरी ओर ई-वे बिल में मंदी आई, जो गतिशीलता प्रतिबंधों और आगामी महीनों में जीएसटी संग्रह में संभावित कमी की ओर इशारा करता है। गतिशीलता में कमी का

<sup>5</sup> आवर वर्ल्ड इन डेटा।

असर अप्रैल के दौरान टोल संग्रह की मात्रा पर भी दिखा। कृषि क्षेत्र में, मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग माह के दौरान कम हो गई, जो कृषि श्रमिकों की बढ़ती मांग का संकेत है। औद्योगिक गतिविधि का जहाँ तक प्रश्न है, विद्युत की मांग स्थिर है। परिवहन सुदृढ़ बना हुआ है, जैसा कि महामारी के कारण आवश्यक चिकित्सा सामग्री की मांग में आए उछाल से समर्थित माल दुलाई में वृद्धि से परिलक्षित होता है। बाह्य मोर्चे पर, अप्रैल में पण्य निर्यात और आयात में 195.7 प्रतिशत और 167.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो निम्न आधार प्रभाव को दर्शाता है, साथ ही बाह्य और घरेलू दोनों प्रकार की मांग में सुधार भी इंगित करता है। अप्रैल में कुल डिजिटल लेनदेन का मूल्य पूर्ववत बना रहा। वित्तीय स्थितियां सामान्यतः अनुकूल और सुधार के सहायक रही हैं।

1.44 भावी स्थिति देखें तो उभरते सीपीआई मुद्रास्फीति वक्र पर ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दोनों दबाव पड़ने की संभावना है। खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति पर 2021 में दक्षिण-पश्चिम मानसून की आवधिक और स्थानिक प्रगति का महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। दूसरा, केंद्र और राज्यों की समन्वित कार्रवाई द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर घरेलू करों के भार से कुछ छूट मिलने के कारण राहत मिल सकती है, यद्यपि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें अस्थिर बनी रहीं। तीसरा, उच्च अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें और सहायक व्यवस्थाओं (लॉजिस्टिक्स) की लागत मिलकर विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट कीमत दबाव बढ़ा सकते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति औसत 5 प्रतिशत रहने की प्रत्याशा है- ति1:2021-22 में 5.2 प्रतिशत; ति2:2021-22 में 5.2 प्रतिशत; ति3:2021-22 में 4.4 प्रतिशत और ति4:2021-22 में 5.1 प्रतिशत, जबकि जोखिम मोटे तौर पर संतुलित बने रहेंगे। अप्रैल 2021 के दौरान अनुकूल आधार प्रभावों के कारण मुद्रास्फीति घट गई।

1.45 2021-22 में भारत के बाह्य क्षेत्र पर वैश्विक घटनाक्रम और उनके प्रसार-प्रभाव का असर रहने की संभावना है। भारत

के पण्य निर्यात और आयात में भले ही सुधार के आरंभिक संकेत दिखाई दे रहे हों, लेकिन कोविड-19 संक्रमणों में पुनः वृद्धि के कारण खराब होता वैश्विक व्यापार वातावरण बाह्य मांग पर दबाव डाल सकता है। महामारी के परिदृश्य में उपजे अवसरों का लाभ उठाते हुए, घरेलू फर्मों को अपेक्षित कौशल उन्नयन और शोध व विकास क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के पूंजी-गहन क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी में अधिक भागीदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत सरकार का जोर मूल्यवर्धन, उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा जीवीसी में घरेलू उद्योगों के जुड़ाव को बढ़ावा देने पर है। इसकी तैयारी के लिए, उल्टी शुल्क संरचना जिसके तहत पीएलआई क्षेत्रों में तैयार माल की तुलना में इनपुट के लिए अधिक दर पर कर लगाया जाता है, को सुधारने की जरूरत है ताकि बड़ी फर्मों को अपना उत्पादन आधार भारत में अंतरित करने और बड़े पैमाने की किफायत का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राज्यों की औद्योगिक नीति/निर्यात नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों में 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)' योजना<sup>6</sup> के समेकन से भी निर्यात को बढ़ावा मिलना चाहिए। निर्यात वृद्धि और जीवीसी में भागीदारी को बढ़ाने के लिए व्यापार सुविधाजनक बनाने पर विभिन्न राष्ट्रों और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ नीतिगत चर्चा, नए व्यापार समझौते और प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को बेहतर करना भी एक प्राथमिकता है। औषधि क्षेत्र में, भारत को एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडियेंट (एपीआई) के घरेलू उत्पादन पर जोर देने के साथ-साथ घरेलू औषधीय निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन में अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। सुदृढ़ सीमापारीय आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए कंटेनरों के स्वदेशी उत्पादन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

<sup>6</sup> यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक पहल है, जिसकी परिकल्पना एक जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य निर्यात की संभावना वाले उत्पादों की पहचान करके, निर्यात से जुड़ी बाधाओं को दूर करके, स्थानीय निर्यातकों / निर्माताओं को सहयोग देकर देश के प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र का रूप देना और जिले में निर्यात / विनिर्माण / सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के बाहर संभावित खरीदारों को ढूँढना और रोजगार पैदा करना है।

1.46 डिजिटल परिचालनों और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग के बीच आईटी सेवाओं के निर्यात के सुदृढ़ बने रहने की संभावना है। प्रमुख आईटी निर्यातक कंपनियों ने विश्व की अग्रणी कंपनियों के साथ नई ग्राहक रणनीतिक साझेदारी कर ली है। वैश्विक समुत्थान की उम्मीद में आईटी सेवाओं पर व्यय का बढ़ना तय है और 2021 में वैश्विक आईटी सेवाओं पर व्यय में 9.0 प्रतिशत की योजनाबद्ध वृद्धि से भी भारतीय आईटी कंपनियों के निर्यात को फायदा होने की संभावना है<sup>7</sup>।

1.47 समुत्थान की संभावना को और बेहतर करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है राजकोषीय नीति का रुखा आधार-संरचना पर दिए गए बल से उत्पादनपूर्व और उत्पादनोत्तर सहबद्धताओं के उपयोग द्वारा गतिविधि में समुत्थान को व्यापक करने वाली स्थितियों का निर्माण हो सकता है। राष्ट्रीय आधार-संरचना पाइपलाइन (एनआईपी) प्रयास के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण (फाइनेंस) करने के लिए 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित ₹20,000 करोड़ के पूंजीगत आधार वाली एक विकास वित्त संस्था (डीएफआई) का लक्ष्य दीर्घावधि परियोजना वित्तपोषण की समस्या को दूर करना है। अर्थव्यवस्था में कारोबार करने को सुगम बनाने संबंधी कदमों पर भी कार्य हो रहा है। विशेषतः संविदा प्रवर्तन (एन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स) और सीमा पार व्यापार (अर्थात् वस्तुओं के निर्यात व आयात की सहायक (लॉजिस्टिकल) प्रक्रिया) पर नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्थान (रैंकिंग) और उन्नत हो। समयपूर्व राजकोषीय सख्ती से समुत्थान के प्रति जोखिम को भाँपते हुए 2021-22 में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को गत वर्ष के 9.4 प्रतिशत से घटाकर जीडीपी के 6.8 प्रतिशत पर बजटित करते हुए और क्रमशः 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक या उससे नीचे लाने के लिए केंद्र सरकार ने क्रमिक राजकोषीय समेकन का मार्ग चुना है। बेहतर अनुपालन और आस्ति मौद्रिकीकरण एवं विनिवेश के सहारे कर राजस्व में बढ़े हुए उछाल से पूंजीगत परिव्यय (पूँजीगत व्यय में से ऋणों व अग्रिमों को घटाकर), जिसमें 54.7 प्रतिशत

की वृद्धि का प्रावधान है, में सहायता मिलने की उम्मीद है। 15वें वित्त आयोग के 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य को देखते हुए राज्यों ने 2021-22 में जीएफडी में लगभग 3.2 प्रतिशत के समेकन (17 राज्यों के बजट पर आधारित) का प्रावधान किया है। महामारी की दूसरी लहर से निपटने हेतु प्रतिचक्रीय अवलंब प्रदान करने के लिए राज्य अधिक उधार लेने को प्रेरित हो सकते हैं।

1.48 राज्य वित्त पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए, अप्रैल 2020 में रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा 31 मार्च 2020 के स्तर से 60 प्रतिशत अधिक कर दी। इसे और 6 महीने अर्थात् 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया और फिर, राज्य अर्थोपाय अग्रिम सलाहकार समिति (2021) [अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव] की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान अंतरिम सीमा और छह महीने अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई। ओवरड्राफ्ट के लिए दिनों की संख्या 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई थी जिसे मई 2021 में सितंबर 2021 तक विस्तार दिया गया। आगे, रिजर्व बैंक ने समेकित ऋण शोधित निधि (सीएसएफ) से आहरण संबंधी नियमों में ढील दी ताकि बाजार उधार के अपने शोधन (रिडेम्पशन) का एक वृहत्तर अंश राज्य पूरा कर सकें। 2021-22 के लिए 'पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' की योजना के अंतर्गत केंद्र ने ब्याज-मुक्त 50-वर्षीय ऋण के रूप में ₹15,000 करोड़ आबंटित किए हैं जो महामारी में पूँजीगत व्यय के लिए *आत्मनिर्भर भारत* पैकेज के अंश के रूप में राज्यों को दिए ₹11,830 करोड़ के अतिरिक्त है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र ने राज्यों को वर्ष 2021-22 के लिए जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के निवल बाजार उधार की अनुमति दी है इस गुंजाइश के साथ कि विद्युत क्षेत्र में सुधार के पूरा होने पर 4 प्रतिशत से अधिक जा सकते हैं।

1.49 2021-22 में मौद्रिक नीति का संचालन उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होगा जिसमें मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर सुनिश्चित करते हुए झुकाव इस पर रहेगा कि

<sup>7</sup> गार्टनर, अप्रैल 2021।

तब तक वृद्धि के लिए यह सहायक बना रहे जब तक वृद्धि टिकाऊ रूप से आगे न बढ़ने लगे। सरकार ने अगले पांच वर्ष (अप्रैल 2021 - मार्च 2026) के लिए निचली व ऊपरी सहाय सीमा को क्रमशः 2 और 6 प्रतिशत रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा है जो न केवल वर्तमान ढाँचे की विश्वसनीयता बल्कि समष्टि-आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में इसकी भूमिका का भी सूचक है। अप्रैल 2021 के अपने संकल्प में, एमपीसी ने एकमत होकर निर्णय लिया कि पॉलिसी रिपो रेट को अपरिवर्तित रखा जाए एवं वृद्धि को सतत बनाए रखने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावी रुख जारी रखा जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहे।

1.50 रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि मौद्रिक नीति के रुख के अनुसार 2021-22 में प्रणाली स्तरीय चलनिधि सुविधाजनक रहे एवं मौद्रिक संचरण निर्बाध होता रहे और साथ ही वित्तीय स्थिरता कायम रहे। इसका उदाहरण है 2021-22 में द्वितीयक बाजार जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) की शुरुआत जिसके तहत रिज़र्व बैंक ने प्रारंभ में ही निश्चित राशि की जी-सेक के खुला बाजार क्रय के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है ताकि अनुकूल स्थितियों में प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) का स्थिर व सुसंगत विकास हो सके। जी-एसएपी 1.0 परिचालनों के सकारात्मक प्रसार-प्रभाव को वित्तीय बाजारों के उन हिस्सों के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है जो कीमत-निर्धारण मानक के तौर पर जी-सेक प्रतिफल वक्र पर भरोसा करते हैं। ₹1 लाख करोड़ के जी-एसएपी के पहले खंड का स्वागत हुआ है तथा जी-सेक यील्ड के विकास पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथ ही, जी-सेक बाजार को और गहरा करने के प्रयास भी चल रहे हैं जिसमें खुदरा सहभागिता बढ़ी हुई हो। एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत, जिससे भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता है, रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार – प्राथमिक व द्वितीयक- में ऑनलाइन खुदरा सहभागिता की घोषणा की जिसमें रिज़र्व बैंक के यहाँ श्रेष्ठ (गिल्ट) प्रतिभूति खाता ('रिटेल डायरेक्ट') खोलने की सुविधा है।

1.51 दूसरी लहर को तेज होता देख रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2021 को महामारी से लड़ाई के लिए नपी-तुली सुविचारित

रणनीति के पहले हिस्से के रूप में कई कदमों की घोषणा की जिसमें सबसे छोटे व सबसे कमजोर पर ध्यान दिया गया है। यह देखते हुए कि दूसरी लहर, ऋण चुकौती में कठिनाइयां पैदा कर सकती है, बैंक ने समाधान संरचना (रिसॉल्यूशन फ्रेमवर्क) 2.0 की घोषणा की जिसमें ₹25 करोड़ की एक्सपोजर सीमा में व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों एवं एमएसएमई द्वारा लिए गए ऋण की पुनः संरचना की अनुमति है। एमएसएमई को दिए गए ताज़ा ऋण (फ्रेश लेंडिंग) को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) से समतुल्य छूट की अनुमति दी गई। 2021 मार्च-अंत तक ₹25 करोड़ तक के कुल ऋण संविभाग वाले लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) – एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य द्वारा दिए ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) हेतु पात्र बनाया गया और ऐसे ऋणों को 2021 के दिसंबर-अंत तक आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) अपेक्षाओं के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाया जा सकता है। एनपीए हेतु विशिष्ट प्रावधान करने के लिए बैंकों को अपने पास 2020 के अंत में उपलब्ध चल प्रावधानित राशियों (फ्लोटिंग प्रोविज़न्स)/ प्रतिचक्रिय प्रावधानीय बफर के 100 प्रतिशत के उपयोग की भी अनुमति दी गई। दूसरी लहर के चलते आवाजाही में लगे प्रतिबंधों को देखते हुए विनियमित इकाइयों (आरई) को कहा गया कि दिसंबर 2021 तक उन खातों में परिचालन न रोके जिनका आवधिक केवाईसी अद्यतनीकरण लंबित (अपडेशन पेंडिंग) है।

1.52 देश में कोविड संबंधी स्वास्थ्य सेवा की आधार संरचना व सेवाओं को बढ़ाने हेतु तत्काल चलनिधि की व्यवस्था को बल देने के लिए रिपो रेट पर तीन वर्ष तक की अवधि के लिए ₹50,000 करोड़ का एक सदा-सुलभ चलनिधि अवसर (ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो) 2021-22 के अंत तक उपलब्ध कराया गया। प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के ताज़ा उधार (फ्रेश लेंडिंग) हेतु नियोजित किए जाने के लिए एसएफबी के लिए रिपो रेट पर ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन-वर्षीय दीर्घवाधि रिपो परिचालन (एसएलटीआरओ) संचलित करने के भी निर्णय लिए गए। प्रणाली-स्तरीय चलनिधि को और बढ़ाने तथा प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) के सुसंगत विकास में सहायता के लिए जी-एसएपी 1.0 के तहत ₹35,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के दूसरे क्रय की घोषणा की गई।

1.53 23 मार्च 2021 को आस्ति वर्गीकरण विराम पर अंतरिम स्थगन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हटा लिए जाने के साथ ही आने वाली तिमाहियों में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी और अधिक प्रवाधानीकरण की तैयारी की आवश्यकता होगी। अधिस्थगन अवधि (1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020) में ऋणों पर प्रभारित ब्याज पर ब्याज की छूट से भी उधार देने वाली संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। तथापि उच्चतर पूँजी बफ़र, वसूली में सुधार और लाभर्जकता की वापसी के कारण वे तुलन पत्रों में दबाव को संभालने की बेहतर स्थिति में हैं। दबाव परीक्षण बता रहे हैं कि अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में भी भारतीय बैंकों के पास समग्र स्तर पर पर्याप्त पूँजी है। बैंक-वार तथा प्रणाली-व्यापी पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण नाजुक क्षेत्रों की भविष्योन्मुखी पहचान का संकेत देते हैं।

1.54 विनियामक एवं पर्यवेक्षी क्षेत्र में 2021-22 में कई कदमों के लागू होने की प्रत्याशा है यथा, सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) में लगी सभी विनियमित इकाइयों पर लागू विनियमावली की समीक्षा; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लाभांश वितरण पर दिशा निदेश और उनके लिए आकार-आधारित विनियम। एक ओर जहाँ फिर से आ खड़ी महामारी के परिणामों पर कार्रवाई के लिए अपेक्षित विनियामक कदम उठाए जा रहे हैं, उम्मीद है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत दिवाला प्रक्रिया की फिर से शुरुआत और एमएसएमई को सुगमतर समाधान माध्यम देने के लिए पहले से एक पैकेजबद्ध दिवाला व्यवस्था से उधारदाताओं द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के सार्थक समाधान पर फिर से ध्यान जाएगा। परिकल्पित बैड बैंक, ऋण जोखिम अंतरण के लिए बाजार-आधारित प्रणाली विकसित करने हेतु विनियामक उपायों जैसे प्रतिभूतिकरण, ऋण एक्सपोजरों के अंतरण और द्वितीयक ऋण बाजार के विकास से बैंकों के तुलन पत्र से दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने में सहायता मिल सकती है।

1.55 जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति सहित निगरानी और आश्वासन कार्यों के प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) आकलन और कारोबारी रणनीति/मॉडलों को भी और मजबूत करने के कदम उठाए जाएंगे। विवरणियों की वर्तमान संरचना की समीक्षा और समेकन द्वारा सभी पर्यवेक्षित इकाइयों (एसई) हेतु पर्यवेक्षी डेटा संरचना के एकीकरण के जरिये पर्यवेक्षी विवरणी प्रणाली को सुगम करने के प्रयास किए जाएंगे। नवोन्मेषी और आरोह्य (स्केलेबल) पर्यवेक्षी तकनीक (सुपटेक) अपनाकर पर्यवेक्षी प्रक्रिया की क्षमता व प्रभाव में और वृद्धि की जाएगी। पूर्व चेतावनी संकेत (ईडबल्यूएस) संरचना के उन्नयन, धोखाधड़ी अभिशासन और प्रतिसाद प्रणालियों के सुदृढीकरण, लेन-देनों की निगरानी हेतु डेटा विश्लेषण के संवर्धन, धोखाधड़ी के लिए समर्पित बाजार आसूचना इकाई की शुरुआत तथा प्रत्येक धोखाधड़ी (फ्रॉड) के लिए अलग नंबर जेनरेट करने वाली स्वचालित प्रणाली के कार्यान्वयन द्वारा धोखाधड़ी (फ्रॉड) जोखिम प्रबंधन प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। एसई में लेखा परीक्षा को सुदृढ करने के लिए वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर सुसंगत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निर्दिष्ट विनियमावली की योजना है: सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश 2020; और आईटी आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश। एक वेब-आधारित एप्लीकेशन पोर्टल अर्थात् एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रेकिंग प्रणाली (आईसीएमटीएस) को कार्यान्वित किया जाएगा ताकि सभी एसई में अनुपालन निगरानी और अधिक सक्षम व सुसंगत हो।

1.56 वैश्विक महामारी में वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक अबाध रूप से पहुँचाने में कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल<sup>8</sup> सामने आया। कोविड-19 के प्रभाव ने विश्व में बैंकिंग कारोबार के

<sup>8</sup> वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने 2006 में बीसी मॉडल प्रारंभ किया था।

प्रतिमान बदल डाले जिसमें वित्तीय समावेश की जड़ें गहरी करने में डिजिटल माध्यम की अधिकाधिक भूमिका है। इस दिशा में हुई प्रगति के आधार पर, बीसी मॉडल को और मजबूत बनाया जाएगा जिससे इस क्षेत्र की उभरती जरूरतों व मांगों के अनुसार यह ढल सके। देश में वित्तीय समावेश की हद का आकलन करने के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा एक वित्तीय समावेश सूचकांक (एफआई इंडेक्स) तैयार करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसे जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा।

1.57 महामारी के दौरान शिकायत निवारण व्यवस्था 24x7 उपलब्ध रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लॉकडाउन व चरणबद्ध अनलॉक में भी विनियमित इकाइयों (आरई) के विरुद्ध शिकायतों पर समय से तथा पर्याप्त ध्यान दिया जाए। रिजर्व बैंक ग्राहक सेवा को और बेहतर करने पर ध्यान देगा और इसके लिए बैंकों द्वारा शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की संरचना के अंतर्गत बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण पर शिक्षा व जागरूकता प्रयासों को भी वर्ष भर जारी रखा जाएगा।

1.58 डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में, एक नवोन्मेष केंद्र, एक विनियामकीय परीक्षण क्षेत्र (सैंडबॉक्स) और ऑफ़लाइन पेमेंट सॉल्यूशन जैसे विभिन्न प्रयास जारी हैं ताकि डिजिटल परितंत्र में भारत अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रख सके। रिजर्व बैंक बैंकों, एटीएम और बीसी की लोकेशन बताने वाली जिओ-टैगिंग संरचना को विस्तार देकर इसमें भुगतान प्रणाली स्पर्श बिंदुओं ( पेमेंट सिस्टम टच प्वाइंट्स) को कवर करने की प्रक्रिया में है जिससे देश भर में उनके सटीक अवस्थान का पता चल सकेगा। देशों के बीच भुगतान व्यवस्थाओं को बढ़ाने के जी-20 अधिदेश के अनुसार देशों के बीच लेन-देन में सहायता के लिए भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली के उपयोग की संभावना की पड़ताल की जा रही है तथा आने वाले धन-प्रेषण के मार्गों व प्रभारों की समीक्षा की जाएगी।

आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, बैंकेतर भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा की जाने वाली आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन की एक विनियामक संरचना कार्यान्वित की जाएगी।

1.59 भारत की वित्तीय प्रणाली में 2021-22 में फिनटेक हेतु संभावनाएं डिजिटल प्रयोग की हद पर निर्भर करेंगी जो कि संबंधित स्वीकृति आधार-संरचना की सुदृढ़ता, उपयोगकर्ताओं (मर्चेन्ट एवं उपभोक्ता दोनों) की वित्तीय साक्षरता व जागरूकता तथा संबंधित ग्राहक संरक्षण और साइबर सुरक्षा के तौर-तरीकों की मजबूती पर निर्भर है। ये सभी कारक डिजिटल पद्धतियों में उपयोक्ताओं के भरोसे को पुख्ता करेंगे। एक अखिल भारतीय नई छत्रप संस्था (न्यू अम्ब्रेला एंटीटी) बनाने के रिजर्व बैंक के प्रयास डिजिटल क्षेत्र में स्पर्धा को तेज करेंगे तथा कुशलता में वृद्धि व सुविधा की दृष्टि से अंतिम-उपयोगकर्ताओं व अन्य सहभागियों के लिए सर्वोत्तम लेकर आएंगे। कार्ड जारीकर्ता बैंकों, फिन-टेक खिलाड़ियों और भुगतान परितंत्र के अन्य हितधारकों के बीच सहयोग से वित्त के एक नए मिश्रित मॉडल के उभरने की संभावना है जो बैंकों की भौगोलिक पहुँच एवं फिन टेक कंपनियों के तकनीकी ज्ञान के उपयोग द्वारा ऋण अंतरालों को दूर करने तथा अंतिम छोर तक पहुँच को बेहतर करने में सहायक होगा।

1.60 संक्षेप में, बीता वर्ष अर्थव्यवस्था पर घाव के दाग छोड़ गया है। 2020-21 के प्रारंभ में दूसरी लहर के बीच व्याप्त निराशा को टीकाकरण के अभियानों द्वारा निर्मित सचेत आशा हटा रही है। वायरस को परास्त करने के गहन राष्ट्रीय प्रयासों का दुनिया के कदमों से कम से कम कुछ सामंजस्य हो रहा है। जैसे-जैसे दुनिया अस्तित्व को बचाना सीखते हुए अनुकूलन कर रही है, देश टीका राष्ट्रवाद से पीछे हट रहे हैं। वैश्विक महामारी से युद्ध के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास के परिणाम निश्चित ही अलग-अलग देशों द्वारा अपने बूते लड़ी जा रही लड़ाइयों से बेहतर होंगे। दृढ़, स्थायी और समावेशी विकास का जी20 लक्ष्य हमारी नज़रों और पहुँच के भीतर हो सकता है।